बड़े शहरों से कस्बों तक चलाई जाएंगी निजी ई-बसें : योगी

- सिटी बस सेवा में निजी ई-बस संचालकों को भी अवसर देगी प्रदेश सरकार
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए किराया, पार्किंग और रूट तय करने के निर्देश

राज्य ब्यूरो, जागरण ● लखनऊ : प्रदेश सरकार पर्यावरण अनुकूल स्वच्छ ईंधन वाली बसों के नगरीय परिवहन का विस्तार करने जा रही है। इसके लिए सिटी बस सेवा में निजी ई-बस संचालकों को भी अवसर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े नगरों से नजदीकी कस्बों तक ई बस सेवा का संचालन कराने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि जनहित में बसों का किराया नियंत्रित किया जाना चाहिए। बसों की पार्किंग की जगह और रूट तय किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को नगर विकास विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं की समीक्षा की और भावी कार्ययोजनाओं को लेकर दिशा-निर्देश दिए। वर्तमान में 15 नगरों में 700 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 15 वर्ष से अधिक पुरानी किसी भी डीजल-सीएनजी बस का उपयोग न होने दिया जाए। ऐसी बसों को स्क्रैप कराकर ई-बसें लाई जाएं। पार्किंग की समस्या पर चिंता जाते हुए निर्देश दिए कि पार्किंग को मांग, स्थान और समय के अनुरूप व्यवस्थित किया जाए। इसके शुल्क में समरूपता होनी चाहिए। पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली न होने दी जाए। स्थानीय व्यापारियों, दुकानों, कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों आदि का बस सेवा का मासिक पास बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि नगरों में विज्ञापन होर्डिंग लगाने में एकरूपता हो। इनसे किसी महापुरुष की प्रतिमा-चित्र आदि विकृत नहीं होने चाहिए। खतरनाक होर्डिंग के स्थान पर इलेक्ट्रानिक डिस्प्ले बोर्ड को वरीयता दी जाए। अवैध होर्डिंग को तत्काल हटवाएं। इसके लिए सभी नगरीय निकायों के लिए स्पष्ट नियामवली होनी चाहिए। योगी ने कहा कि सभी नगरीय निकायों में अचल संपत्तियों के नामांतरण, पंजीयन, वसीयत आदि प्रकरणों के लिए एक समान प्रक्रिया और समान शुल्क की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने जिला मुख्यालय वाले नगर निकायों को स्मार्ट नगर पालिका के रूप में विकसित करने की विस्तृत कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिए। स्मार्ट नगर पालिकाओं में डिजिटल गवर्नेंस, वैल्यू एडेड सिटिजन सर्विस, जलभराव की समस्या की मानिटरिंग, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट प्रकाश प्रबंधन, प्रदर्शनी स्थल, आडिटोरियम, वेंडिंग जोन, डिजिटल लाइब्रेरी, नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पों को प्रोत्साहन जैसे ईज आफ लिविंग संबंधी कार्य कराए जाएं। इन निकायों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार करें। नगर निकायों में जहां कहीं पद रिक्त हैं, तत्काल भर्ती की कार्यवाही करें। जहां आउटसोर्सिंग से तैनाती होनी हो, बिना विलंब प्रक्रिया पूरी करें। बरसात से पहले सभी निकायों में ड्रेनेज व्यवस्था को बेहतर कर लिया जाए।

संबंधित खबर » पेज 2